पहुंच बनाने तथा अपना रोजगार शुरू करने के लिए आकर्षक ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराने की बहुत जरूरत है ।

हरियाणा में महिलाओं का कृषि के उत्पादन में उल्लेखनीय योगदान है । उनकी कुशलता बढ़ाने से नई–नई तकनीकों को अपनाने और फार्म उत्पादन को बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी । यह भी अनुभव किया गया है कि यदि किसानों को जलवायु के अनुकूल खेती की कुशल विधियों और तकनीकों से अवगत कराया जाए और उन्हें सशक्त बनाया जाए तो वे इन विधियो और तकनीकों को अपनाने के प्रति बहुत सजग रहते हैं ।

हरियाणा किसान आयोग को सरकार की सहायता

हरियाणा किसान आयोग सरकार को यह समझाने में सफल रहा है कि नई विधियों को खेती की वर्तमान स्थितियों के अनुकूल बनाने और अनुसंधान में जो कमियां हैं उन्हें दूर करने से खेती से होने वाली आमदनी, कृषि के टिकाऊपन और खाद्य सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है । तदानुसार, सरकार हरियाणा किसान आयोग के सुझावों पर राजी हो गई है और नीचे दिये गये विवरण के अनुसार धनराशि उपलब्ध कराई है :

➢ **कृषि नवोन्मेश निधि**

किसानों द्वारा की गई नई खोजों को पहचानने व उन्हें वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल बनाने के लिए बजट में 3 करोड़ रूपये निर्धारित किये गये हैं ।

➢ **हरियाणा राज्य कृषि अनुसंधान एवं विकास निधि**

सरकार ने अनुसंधान में मौजूद कमियों को दूर करने के लिए 6 करोड़ रूपये आबंटित किये हैं । इसके लिए अनुसंधान परियोजनाएं; विश्वविद्यालयों, कृषि विज्ञान केन्द्र और भारतीय कृषि अनुसंधान परिशद के संस्थान ; राज्य के कृषि, बागवानी, पशु पालन, मत्स्यिकी आदि जैसे विभाग ; और राज्य में मौजूद स्वयं सेवी संगठन, कृषि विज्ञान केन्द्र, सार्वजनिक / अर्द्ध सार्वजनिक और निजी संस्थाए, हरियाणा किसान आयोग व एच. एस. ए. एम. बी. द्वारा पहचाने गये एवं जो अनुसंधान कार्य करने में सक्षम हो के द्वारा पेश की जा सकती है ।

आयोग के प्रकाशन

1. समाचार पत्रिका

हरियाणा किसान आयोग एक तिमाही समाचार पत्रिका प्रकाशित करता है जिसमें आयोग द्वारा प्रकाशित रिपोर्टों तथा अन्य कियाकलापों के बारे में बहुमूल्य जानकारी दी जाती है । इस समाचार पत्रिका में कृषि, बागवानी, मात्स्यिकी, विश्वविद्यालयों / संस्थाओं और अन्य संबंधित विभागों के बारे में भी जानकारी होती है । समाचार पत्रिका में किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए किसी प्रगतिशील किसान की सफलता की कहानी भी प्रकाशित की जाती है । किसान जो नई–नई खोजें करते हैं, इस प्रकाशन में उनके बारे में भी बताया जाता है ।

2. हरियाणा के किसानों से संबंधित योजनाएं

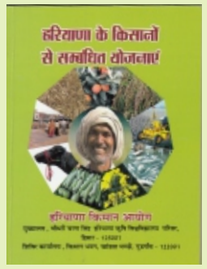

किसानों को सशक्त बनाना हमेशा हरियाणा सरकार तथा भारत सरकार का उद्देश्य रहा है । तदानुसार, किसानों को ऐसी अनेक योजनाओं के माध्यम से सहायता दी जाती है जिनसे उनकी फसलों का उत्पादन, उत्पादकता, होने वाली आमदनी और संसाधन प्रबंध में सहायता मिले । हरियाणा किसान आयोग ने उन सभी प्रशासनिक योजनाओं को संकलित किया है जो हरियाणा में चल रही हैं और किसानों को इन चल रही योजनाओं से अवगत कराने के लिए एक छोटी पुस्तिका प्रकाशित की है । किसानों को सुविधा हो, इसके लिए यह पुस्तिका हिन्दी में छापी गई है । **कृषि विज्ञान केन्द्रों, किसान क्लबों, कृषि, बागवानी, पशु पालन और डेयरी तथा मात्स्यिकी विभाग के कर्मियों के माध्यम से इस पुस्तिका की एक लाख प्रतियां किसानों में बांटी जा चुकी हैं ।**

3. फार्म रिकार्ड का लेखा

फार्म पर होने वाले व्यय और आमदनी को व्यवस्थित ढंग से दैनिक आधार पर ठोस व सही ढंग से रिकार्ड करने से किसानों को बेहतर योजना बनाने और उनकी आमदनी बढ़ाने में बहुत मदद् मिलती है । किसान अपने इन रिकार्डों का उपयोग अपने वित्तीय संसाधनों के कुशल प्रबंधन के लिए कर सकते हैं ।

4. किसानों के लिए उपयोगी सुझाव

हरियाणा राज्य के सामने मिट्टी और पानी के प्रबंधन, वातावरण में असंतुलन, मजूदरों की कमी, उत्पादन विधियों के दक्ष न होने, खेती की लागत में होने वाली बढ़ोतरी तथा घटक उत्पादकता में होने वाली कमी जैसी अनेक जटिल समस्याएं हैं । इसलिए समय आ गया है कि इन समस्याओं से निपटा जाए तथा फसलों के टिकाऊ व उच्च उत्पादन तथा राज्य में कृषि पारिस्थितिक वातावरण को सुधारने के लिए उत्पादन की विधियों को स्थितियों के अनुकूल बनाया जाए। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हरियाणा किसान आयोग ने किसानों के फायदे के लिए यह फ्लायर तैयार किया है ।

मुख्यालयः
हरियाणा किसान आयोग,
अनाज मण्डी, सैक्टर–20,
पंचकुला–134116
दूरभाषः+91–172–2551664, 2551764
फैक्सः+91–172–2551864

शिविर कार्यालयः
हरियाणा किसान आयोग,
किसान भवन,
खाण्डसा मण्डी,
गुडगांव– 122001
दूरभाषः+91–124–2300784

www.haryanakisanayog.org

Printing Centre, Ph. 0172-2702384

हरियाणा किसान आयोग

एक झलक

राज्य के किसानों की सेवा में एक प्रगतिशील कदम के रूप में हरियाणा सरकार ने 15 जुलाई, 2010 को हरियाणा फार्मर कमिशन स्थापित करने का फैसला किया । इसे सामान्य तौर पर ''हरियाणा किसान आयोग'' के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्यालय अनाज मण्डी, सैक्टर–20, पंचकुला में है तथा शिविर कार्यालय किसान भवन, खांड़सा मण्डी, गुडगांव में है ।

इस आयोग के अध्यक्ष भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्व महानिदेशक तथा भारत सरकार के कृषि एवं शिक्षा विभाग के सचिव, पद्म भूषण डॉ. आर. एस. परोदा हैं । इसके सदस्य है श्री रोशन लाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार तथा डॉ. के. एस. खोखर कुलपति, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार । डॉ आर एस दलाल इसके सदस्य सचिव हैं ।

उद्देश्य

1. हरियाणा की खेती, इसके निष्पादन, मजबूती और कमजोरियों की मौजूदा स्थिति की समीक्षा करना, विभिन्न कृषि जलवायु वाले उप–क्षेत्रों में किसानों की विभिन्न श्रेणियों की दशा का मूल्यांकन करना और राज्य में कृषि के टिकाऊ व समान विकास के लिए वृहत कार्यनीति तैयार करना ।
2. खेती से होने वाली आमदनी के कम होने के लिए जिम्मेदार कारणों का विश्लेशण करना और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए उपाय सुझाना ।
3. राज्य में खेती की मुख्य प्रणालियों की उत्पादकता, उनसे होने वाले फायदे, टिकाऊपन और स्थिरता को बढ़ाने के लिए विधियां बताना ।
4. व्यावहारिक और प्रतियोगी फसलों (बागवानी फसलों सहित) – पशुधन – मछली पालन की समेकित प्रणाली के बारे में सुझाव देना और खेती तथा इससे जुड़े अन्य क्षेत्रों के बीच तालमेल स्थापित करना ।
5. बीजों, रासायनिक खादों, कीटनाशकों व ऋण दिलाने की कार्य प्रणाली तथा निवेश उपयोग की मौजूदा कुशलता की जांच करना और इसमें सुधार के लिए उपाय सुझाना।
6. खेती में पानी के इस्तेमाल के मौजूदा हालात की समीक्षा करना और इसकी कुशलता में सुधार लाने के उपाय बताना ।

सरकार को पेश की गई रिपोर्टें

प्रतिश्ठित वैज्ञानिकों और विशेशज्ञों से युक्त विभिन्न तकनीकी कार्यदलों ने सरकार को आगे भेजे जाने के लिए अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं । उम्मीद है कि इन रिपोर्टों से खेती को सक्षम और फायदेमंद पेशा बनाने के लिए कार्यनीति योजना बनाने में मदद मिलेगी ।

(1) हरियाणा राज्य कृषि नीति की मसौदा रिपोर्ट

(2) किसानों के साथ चर्चा पर आधारित नीतिगत बिन्दुओं और विकल्पों पर कार्यदल की रिपोर्ट

(3) संरक्षण कृषि पर कार्यदल की रिपोर्ट

(4) हरियाणा में प्राकृतिक संसाधन प्रबंध पर कार्यदल की रिपोर्ट

(5) हरियाणा में मछली पालन के विकास पर कार्यदल की रिपोर्ट

(6) हरियाणा में बागवानी के विकास पर कार्यदल की रिपोर्ट

(7) हरियाणा में सुरक्षित खेती के विकास पर कार्यदल की रिपोर्ट

(8) हरियाणा में पशु पालन के विकास पर कार्यदल की रिपोर्ट

(9) हरियाणा में फसलों की उत्पादकता बढ़ाने पर कार्यदल की रिपोर्ट

(10) हरियाणा में बारानी क्षेत्र के विकास पर कार्यदल की रिपोर्ट

(11) हरियाणा में किसानों का बाजार से सम्पर्क पर कार्यदल की रिपोर्ट

तकनीकी कार्यदल

1. हरियाणा में कटाई उपरांत प्रौद्योगिकी व मूल्यवर्धन
2. हरियाणा में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देना
3. हरियाणा में कृषि विस्तार

राज्य सरकार द्वारा स्वीकार की गई आयोग की महत्वपूर्ण सिफारिशें

- राज्य कृषि नीति को अपनाया गया
- कृषि ऋणों पर ब्याज की दरें घटाकर 4 प्रतिशत की गईं
- कृषि ऋण लेने पर स्टैम्प ड्यूटी समाप्त की गई
- सभी किसानों को मिट्टी के हालात के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किये गये
- लगभग सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये गये
- राज्य पशुधन मिशन की शुरूआत हुई
- मछली पालन तालाबों के लिए पानी की दरें बहुत कम की गईं
- चावल की खेती वाले क्षेत्र को कम करने और चावल–गेहूं प्रणाली में विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए गए
- चारा बीज उत्पादन के लिए रोलिंग प्लान तैयार किया जा रहा है
- ए. पी. एम. सी. अधिनियम से फलों और सब्जियों को हटाए जाने के लिए सुधार लाए जा रहे है
- फलों और सब्जियों पर मण्डी शुल्क माफ किया गया
- ए. डी. ओ. के वेतनमान संशोधित किये गये

किसानों, योजनाकारों और वैज्ञानिकों के बीच पारस्परिक संवाद

किसानों की समस्याओं, उनकी आवश्यकताओं और उनकी क्षमता में होने वाले बदलावों को समझने के लिए हरियाणा किसान आयोग ने किसानों के साथ कार्यशालाएं और पारस्परिक संवाद कार्यक्रम आयोजित किये गये जिनमें आपसी चर्चा के लिए योजनाकारों और वैज्ञानिकों को भी आमंत्रित किया गया । इनमें से कुछ निम्नानुसार हैं :

क. आयोजित कार्यशालाएं

हरियाणा किसान आयोग ने अब तक निम्नलिखित कार्यशालाएं आयोजित की हैं :

1. चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार में 23 दिसम्बर, 2011 को ''किसान प्रेरित नवप्रवर्तन'' विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला
2. हिसार में 7 मई, 2011 को खेतीहर महिलाओं या खेती से जुड़ी महिलाओं के साथ एक कार्यशाला आयोजित की गई
3. करनाल जिले के तरावड़ी गांव में 28 सितम्बर, 2012 को हरियाणा में जलवायु के अनुकूल खेती की कुशल विधियों पर किसानों के सशक्तीकरण के लिए कार्यशाला आयोजित की गई
4. राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल में 22 दिसम्बर, 2012 को ''कृषि में विविधीकरण के माध्यम से सम्पन्नता'' विषय पर सेमिनार आयोजित हुआ

5. 6 जून, 2013 को जैविक खेती पर एक कार्यशाला आयोजित की गई
6. एन. ए. एस. सी. परिसर, नई दिल्ली में 3–5 सितम्बर, 2013 को ''खेती से जुड़े नवप्रवर्तनों को अनुकूल बनाना'' विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन
7. महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक, हरियाणा में 21 दिसम्बर, 2013 को ''खेती में युवाओं के लिए अवसर'' विषय पर सेमिनार का आयोजन
8. एच. ए. एम. ई. टी. आई., जींद में 07 मार्च, 2014 को कपास में समन्वित नाशीजीव प्रबंध पर विचारोत्तेजक सत्र
9. चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार में 09 जून, 2014 को ''हरियाणा के लिए कटाई उपरांत प्रौद्योगिकी और मूल्यवर्धन'' विषय पर कार्यशाला
10. किसान भवन, पंचकुला में 24 जून, 2014 को मधुमक्खी पालन पर कार्यशाला।

ख. किसानों के साथ महत्वपूर्ण बैठकें

1. राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल में 9 सितम्बर, 2010 को डेयरी किसानों के साथ बैठक
2. केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, करनाल में 8 अक्तूबर, 2010 को किसानों के साथ बैठक
3. राज्य के प्रत्येक प्रशासनिक प्रभाग में किसानों के साथ चार परामर्श बैठकें आयोजित हुई
4. हिसार में 3 अप्रैल, 2011 और 25 फरवरी, 2012 को राज्य के प्रगतिशील किसानों के साथ बैठकें आयोजित हुईं
5. राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल में 20 मई, 2013 को ''मक्का और जलवायु की दृष्टि से अनुकूल विधियों को अपनाकर लचीला विविधीकरण विकल्प को बढ़ावा देने'' विषय पर स्टेकहोल्डरों से परामर्श
6. दिनांक 5 जून, 2013 को हरियाणा में सुरक्षित खेती पर किसानों के साथ पारस्परिक चर्चा का आयोजन
7. जींद जिले में कपास में नाशकजीव प्रबंध से जुड़ी खेतिहर महिलाओं के साथ 7 मार्च, 2014 और 30 जून, 2014 को एक बैठक का आयोजन

हरियाणा किसान आयोग की कार्यशालाओं/ आपसी चर्चाओं से किसानों के लगातार सम्पर्क का बहुत फायदा हुआ है और इससे किसानों की नई–नई खोजें करने की क्षमता तथा खेती के समग्र विकास के लिए नई तकनीकों को अपनाने और इस प्रकार अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए इन्हें प्रेरित करने में बहुत मदद मिली है । इसी प्रकार गांवों के नौजवानों ने भी अपनी उद्यमशीलता का परिचय दिया है । तथापि, इन नौजवानों की कुशलता को सुधारने, बाजार तक उनकी